(b) whether Government are aware of the fact that the enhancement of the export ceiling to 75 million kg will push up pirces further and also create scarcity of yarn in India;

(c) whether it is a fact that the policy that yarn exports would be permitted only against the import of cotton has not yet been properly implemented;

(d) whether Government are aware of the difficulties faced by the garment manufacturers as well as the handloom and hosiery industries owing to the sale of cotton yarn in the overseas market this year; and

(e) if so, what measures are proposed to be taken to mitigate their hardships?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) Increase in prices can not be attributed to exports only a small percentage of yarn production has been allowed for exports.

(c) The imports of cotton against exports of yarn have been allowed under the Advance Licencing Scheme.

(d) and (e) Do not arise in view of (b) above.

श्री निवासपुरी, दिल्ली में एक महिला की हत्या

3187. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनिवासपुरी, दिल्ली की 44 वर्षीय सरिता अग्रवाल की हाल में की गई नृशंस हत्या के संबंध में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अभी तक कोई भी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक

3188. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटकपुर, बाग मोची, नानक पुरा, नई दिल्ली में बना पंजाब नेशनल बैंक की शाखा भूतपूर्व मैनेजर द्वारा किए गए घपले की निशानी है, यदि हां, तो क्या भूतपूर्व मैनेजर द्वारा प्लाट के कागजातों की जांच की गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या भूतपूर्व मैनेजर तथा प्लाट के मालिक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाणपत्र लिया था, यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो शीघ्र ही सेवा से निवृत्त होने वाला था, यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है, और

(ग) बैंक द्वारा उक्त शाखा के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई और क्या बैंक द्वारा प्लाट का किराया दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा प्लाट के मालिक को दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसकी मोचीबाग, नानकपुरा, नई दिल्ली शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने, उस प्लाट के, जहां पर बैंक की शाखा स्थित है, हक-विलेखों का सत्यापन नहीं किया था/जांच नहीं की थी। यह काम मालिक को मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर करने से पूर्व किया जाना था। इस चूक के लिए, शाखा प्रबन्धक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

(ख) बैंक के अनुसार, उसके रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चल सके कि मकान मालिक ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया था, अथवा नहीं।

(ग) शाखा प्रबन्धक की सिफारिश पर मकान मालिकों कोई परिसर के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 3 लाख रुपए का सावधि ऋण मंजूर किया गया था। 10,776/-रुपए के मासिक किराए मे से 7689/-रुपए की रकम, सावधि ऋण की चुनौती के रूप में विनियोजित कर ली जाती थी। मकान मालिकों मे से एक की जून, 1986 मे मृत्यु हो गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब मकान मालकिन के स्वामित्व पर विवाद खडा कर दिया है। यह मामला अंतिम निर्णय के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी के पास विचाराधीन पड़ा है। बैंक, जनवरी, 1987 से किसी को भी, किराया नही दे रहा है। मकान मालकिन से सिविल न्यायालय से अपना हक सिद्ध/घोषित करवाने के लिए कह दिया गया है।

Persons killed by extremists in different states

3189. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of persons killed by the extremists in Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi and Uttar Pradesh since 1982 year-wise; and

(b) the number of terrorists killed/detained/convicted and those who escaped from custody from the above places since 1982?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Staff Inspection Unit

3190 SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has established a machinery called Staff Inspection Unit to assess the staff strength in various Ministries and departments;

(b) if so, whether the said Unit has visited the office of the Registrar General of India at New Delhi and its subordinate offices like Census Directorates in different States and Union Territories;

(c) whether the Unit has submitted any report to Government; and

(d) if so, what are its recommendations and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) and (b) Yes, Sir. The Staff Inspection Unit (SIU) team visited the office of the Registrar General and Census Commissioner, India (Headquarters Office, New Delhi including Language Division, Calcutta) and five selected representative Directorates of Census Operations with the express consent of that office.

(c) and (d) The SIU has submitted a part report in respect of the Group A, B and C posts of the Headquarters Office. The assessed strength is 759 posts against existing 769 posts. The requirement of Group 'D' staff in the Headquarters Office as well as the requirement of manpower in the Directorates of Census Operations is yet to be finalised. The matter is under examination in consultation with the Ministry of Home Affairs.

3191 [*Transferred to the 10th December, 1987*]

Inadequate drainage Channel facilities in Orissa

3192. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drainage channel facilities available